भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-465
उत्तर दिनांक 25.03.2026 को दिया गया

दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंधित विशिष्ट गलियारे

*465. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने विशेषकर राजस्थान और झारखंड सहित देश में दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंधित विशिष्ट गलियारों की स्थापना के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में शुरू की गई 'रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' से रक्षा और 'एयरोस्पेस' क्षेत्रों में भारत को 'हाई-एंड मैग्नेट' के वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी;

(ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा दुर्लभ मृदा अयस्क संसाधनों को बढ़ाने के क्षेत्र में अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड की सुविधाओं को मृदा तत्वों से संबंधित नए गलियारे के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार विशेषकर क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित ओडिशा में दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंधित अन्वेषण, प्रसंस्करण और विनिर्माण अवसंरचना का विकास करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ): सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

*****

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

"दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंधित विशिष्ट गलियारे" के संबंध में श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ व श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी द्वारा पूछे गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *465 के भाग (क) से (ङ), जिसका उत्तर दिनांक 25.03.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में प्रस्तुत विवरण

(क) सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को शामिल करते हुए दुर्लभ मृदा कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की है।

(ख) हां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 26 नवंबर 2025 को सिंटरित दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक (आरईपीएम) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है और इसे दिनांक 15 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किया गया। इस पहल का उद्देश्य भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की एकीकृत दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक (आरईपीएम) विनिर्माण स्थापित करना है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वैश्विक आरईपीएम बाजार में भारत का स्थान एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। इस योजना का उद्देश्य दुर्लभ मृदा ऑक्साइड के प्रसंस्करण से लेकर धातुओं और मिश्र धातुओं के उत्पादन और अंतिम रूप से तैयार चुंबक के विनिर्माण तक, देश के भीतर आरईपीएम की शुरू से अंत तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की विनिर्माण क्षमताओं को स्थापित करना है।

(ग) दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए अन्वेषण गतिविधियों के परिणामस्वरूप भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने देश भर में 763 मिलियन टन संचयी आरईई अयस्क संसाधनों की वृद्धि की है और खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद से विभिन्न निर्धारित (कट-ऑफ) मूल्यों और औसत ग्रेड पर उनका मूल्यांकन किया है (अनुलग्नक-I)।

(घ) आईआरईएल ओडिशा में एक दुर्लभ मृदा निष्कर्षण संयंत्र और केरल के अलुवा में एक दुर्लभ मृदा शोधन संयंत्र प्रचालित करता है, जो दोनों कॉरिडोर पहल के अनुरूप हैं। भारत सरकार का लक्ष्य घरेलू दुर्लभ मृदा क्षमता का विस्तार करने, उन्नत विनिर्माण को बढ़ावा देने और आत्म-निर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत के परिवर्तन को गति देने के लिए नए कॉरिडोर के साथ आईआरईएल सुविधाओं का एकीकरण करना है।

(ङ) हां। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की एक संघटक इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ओडिशा सहित देश के संभावित भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में समुद्र तटीय बालू खनिजों और कठोर चट्टान क्षेत्रों में आरईई संसाधन निर्धारित करने और वृद्धि करने के लिए एकीकृत और बहु-आयामी अन्वेषण कार्य कर रही है। एएमडी वर्तमान में ओडिशा के पुरी जिले सहित देश के तटीय क्षेत्रों में समुद्र तटीय बालू निक्षेप में मोनाज़ाइट (आरईई और थोरियम का एक खनिज) के अतिरिक्त संसाधन निर्धारित करने के लिए अन्वेषण कर रही है। हालांकि, एएमडी द्वारा ओडिशा के क्योंझर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आरईई के लिए अन्वेषण नहीं किया जा रहा है।

इसके अलावा, जीएसआई ने पिछले चार वर्षों (वर्ष 2021-22 से 2024-25) में ओडिशा राज्य में दुर्लभ मृदा तत्वों-दुर्लभ धातुओं (आरईई-आरएम) के लिए 17 खनिज अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। वर्ष 2025-26 में, जीएसआई ने ओडिशा में नयागढ और बालंगीर जिलों में आरईई-आरएम के लिए 3 खनिज अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं (अनुलग्नक-II)। जीएसआई कई वर्षों से ओडिशा के केन्दुझर (क्योंझर) जिले में मैंगनीज, सोना, लोहा, निकल आदि विभिन्न खनिज पदार्थों की अन्वेषण गतिविधियों में संलग्न है। परन्तु, जीएसआई द्वारा क्योंझर जिले में आरईई को लक्षित करते हुए कोई अन्वेषण परियोजना शुरू नहीं की गई है।

*****

अनुलग्नक- I

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद से विभिन्न निर्धारित (कट-ऑफ) मूल्यों और ग्रेड में आरईई के लिए जीएसआई द्वारा संवर्धित राज्य-वार संचयी संसाधन

संसाधन, मिलियन टन में

क्र.सं.	**राज्य**	**आरईई-आरएम**	**क्र.सं.**	**राज्य**	**आरईई-आरएम**
1	असम	30.51	7	महाराष्ट्र	76.6
2	अरुणाचल प्रदेश	2.15	8	राजस्थान	83.59
3	बिहार	81.03	9	उत्तर प्रदेश	0.342
4	गुजरात	459.99	10	तमिलनाडु	4.62
5	झारखंड	0.0092	11	तेलंगाना	10.85
6	कर्नाटक	13.11	12	पश्चिम बंगाल	0.68
				कुल	**763**

अनुलग्नक- II

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक ओडिशा राज्य में जीएसआई द्वारा आरईई-आरएम के संबंध में शुरू की गई खनिज अन्वेषण परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	एफएस वर्ष	राज्य	जिला	खनिज ब्लॉक/क्षेत्र का नाम	यूएनएफसी चरण	खनिज पदार्थ
1	2021-22	ओडिशा	नयागढ़	खुंटापाड़ा-पुरुषोत्तमपुरा	G4	आरईई, आरएम
2		ओडिशा	बौध और सुबर्णपुर	दमामुंडा-बिलासपुर	G4	आरईई, आरएम
3		ओडिशा	कोरापुट	कोरापुट	G4	आरईई, आरएम
4		ओडिशा	बालंगीर	अम्पाली-बडीपुरा-सेंटाला	G4	मूलधातु, ग्रेफाइट और आरईई
5	2022-23	ओडिशा	सुंदरगढ़	गढ़जंजोर	G3	फॉस्फोराइट, आरईई
6		ओडिशा	बौध और सोनपुर	गबजोर	G4	आरईई, आरएम
7		ओडिशा	नयागढ़	नोतारा-बाउलासाही	G4	आरईई, आरएम
8	2023-24	ओडिशा	नयागढ़	खुंटापाड़ा-अरखापाल	G3	आरईई, आरएम
9		ओडिशा	अंगुल	देबीनगर	G4	आरईई
10		ओडिशा	गंजम	कुम्भरझोली-बोराडा	G4	आरईई, आरएम
11	2024-25	ओडिशा	नयागढ़	कोरिएकाहनिया-बौलासाही-बद्भूइन	G3	आरईई, आरएम
12		ओडिशा	नुआपारा	भेला-बाबुपल्ली-उदयबंध	G4	आरईई, आरएम, पीजीई
13		ओडिशा	झारसुगुड़ा	खोल्डीपा-घिचा मुरा	G4	आरईई, आरएम
14		ओडिशा	बौध	पल्सागोरा-पिंडापादर	G4	आरईई, आरएम
15		ओडिशा	कोरापुट	दम्मापरहा-मैथिली	G4	टिन, आरईई
16		ओडिशा	अंगुल	देबीनगर पूर्व	G4	आरईई
17		ओडिशा	नुआपारा	राजना-महूलपादर	G4	आरईई, आरएम, पीजीई
18	2025-26	ओडिशा	नयागढ़	नोतारा-तेंतूलियापल्ली-इकिरी	G3	आरईई, आरएम
19		ओडिशा	नयागढ़	संखेई-तेंतूलियापल्ली-नाचीपुर	G3	आरईई, आरएम
20		ओडिशा	बालंगीर	टेप्रेन-शिबतला	G4	आरईई, आरएम